>

MR. CHAIRMAN: Now we take up matters of urgent public importance. We have only fifteen minutes left and there are 18 matters of urgent public importance. Please take only one minute each. We will be completing this by eight o'clock.

Shri Ashok Argal *ji*, when your name was called, you were absent. Please finish it in one minute.

Title: Regarding enhancement of fee from Rs. 18,000/- to Rs. 60,000/- for issuance of CGHS cards to Ex-MPs.

श्री अशोक अर्गल (भिंड): माननीय सभापति महोदय, संसद के पूर्व सदस्यों का सीजीएचएस कार्ड पहले 18000 रुपये में बनता था। अब 18000 रुपये के स्थान पर उसकी कीमत 60000 रुपये कर दी है। इससे कई पूर्व संसद सदस्य कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार इस पर ध्यान दे। आपको मालूम है कि कई पूर्व संसद सदस्यों की पैंशन ही 8000 रुपये है। 8000 रुपये में उनका खर्चा भी नहीं चल सकता। कई पूर्व संसद सदस्य पैंशन के लिए डिमांड भी करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसमें सुधार होना चाहिए। पहले यह 18000 रुपये में बनता था और अब 60000 रुपये कर दिया है। एकदम से 42000 रुपये बढ़ाना कहीं से न्यायोचित नहीं है। मैं चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार इसमें इंटरफियर करे और इस राशि को कम करे।

*t28

Title: Increasing number of pending cases in Supreme Court and High Courts of the Country.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और कदाचित आप इससे सहमत होंगे। आज देश के सभी राज्यों में आम वादकारियों को, आम आदमी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कानून मंत्रालय के हिसाब से आज की तारीख में 26,16,246 मुकदमे देश के विभिन्न राज्यों की हाई कोर्ट्स में लंबित हैं। 1 जून, 2009 तक सुप्रीम कोर्ट में 50,659 मुकदमे लंबित हैं। लोअर कोर्ट्स में इसकी संख्या राज्यवार - महाराष्ट्र में 40 लाख, पश्चिम बंगाल में 24 लाख, बिहार में 14 लाख, राजस्थान में 12 लाख और दिल्ली में 11.5 लाख है। इसी तरह से हाई कोर्ट्स में यूपी में सर्वाधिक 9,11,858 मुकदमे लंबित हैं; तमिलनाडु में 4,51,496; महाराष्ट्र में 3,69,978 और पश्चिम बंगाल में 3,00,473 मुकदमे लंबित हैं।

MR. CHAIRMAN: What is your demand? What is your suggestion to the Government?

SHRI JAGDAMBIKA PAL : Justice delayed is justice denied. अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर देर में न्याय नहीं मिलता है। आज हाई कोर्ट्स में भी जजेज़ के पद रिक्त हैं और इस नाते उन जजेज़ के पदों को भरा जाए, निश्चित तौर से नए पदों का सृजन किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाएँ, देश में न्यायालयों में लंबित जो मुकदमे हैं, इन मुकदमों की पैन्डैन्सी जो इतनी बड़ी तादाद में लागू है, इसे समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाए। इससे महत्वपूर्ण मुद्दा कोई और नहीं हो सकता।

*t29

Title: Need to implement the action plan formulated for the development of Kabar lake in Bihar.

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदय, बिहार में कावर झील 25 हज़ार हैक्टेयर में है और वहाँ साइबेरियन बड्र्ज़ और दुनिया भर की चिड़ियाँ आती हैं। वे शीतकाल में वहाँ बसेरा करती हैं, चहचहाती हैं। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पिछले वर्षों में इसे पक्षी विहार बनाने के लिए दस करोड़ रुपये दिये। इसके लिए एक कार्य योजना भी बनी पर आज तक उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करते हैं कि यदि उसे पक्षी विहार बनाना है, जिसकी घोषणा उन्होंने की है, तो जो निधि दी है, जो कार्य योजना बनी है, उसका कार्यान्वयन वे करा दें।

*t30

Title: Need to provide computerised reservation centre at Mandiyahu Railway Station on Allahabad − Jaunpur railway section in Uttar Pradesh.

श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के रेलवे स्टेशन मड़ियाहूं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

यह इलाहाबाद-जौनपुर पूर्वोत्तर रेल लाइन पर है। मड़ियाहूं रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को असुविधा का सामना करना पड़ता है। मड़ियाहूं रेलवे स्टेशन तहसील मुख्यालय से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ मड़ियाहूं एक व्यापारिक केन्द्र भी है। इसलिए यहां पर लोगों का बड़ी संख्या में आना-जाना होता है। यहां आरक्षण केन्द्र न होने के कारण लोगों को तहसील मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर जाकर टिकट आरक्षित करवानी पड़ती है। अतः मेरी आपसे मांग है कि मड़ियाहूं रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था करें।

*t31

Title : Need to immediately relase funds sanctioned by the Ministry of Urban Poverty Alleviation for drainage and sewerage work to

Hajipur Municipal Council (City), Bihar.

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद (मुज़फ़्फ़रपुर): सभापति महोदय, मैं अति लोकमहत्व के विषय को उठा रहा हूं।

महोदय, बिहार प्रदेश में हाजीपुर नगर परिषद का एनजीओ के माध्यम से ड्रेनेज एवं सीवेरज का डीपीआर वर्ष 2008 में 90 करोड़ रूपये का बना था। इसे केन्द्र के शहरी विकास मंत्रालय ने वर्ष 2009 में पारित कर दिया था। हाजीपुर शहर की हालत काफी दयनीय है। बरसात के दिनों में जलजमाव के कारण शहर झील में तब्दील हो जाता है। अतः जो राशि केन्द्र सरकार से स्वीकृत हुई है, इसे शीघ्र भेजा जाए ताकि शहरवासियों को जलजमाव से हो रही भीषण कठिनाइयों से निजात मिल सके।

*t32

Title: Damage of 9 lakh tonnes of wheat worth Rs. 60 lakh in FCI Godown at Sasaram (Bihar).

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): सभापति महोदय, मैं शून्य काल में राष्ट्रीय हित के मुद्दे को उठाते हुए 8 जुलाई को दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि पंजाब से नौ हजार टन गेहूं सहरसा, बिहार के एफसीआई गोदाम में स्टोरेज के लिए लाया गया था। लेकिन एफसीआई के अधिकारियों की लापरवाही के कारण सारा गेहूं रैक पर ही सड़ गया। जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रूपये आंकी गई है। इस प्रकरण से संबंधित अधिकारियों पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए तथा राष्ट्र की सम्पत्ति की आगे बरबादी न हो, इसके लिए गेहूं को रेल से लाने की समुचित व्यवस्था की जाए। इसे एफसीआई अथवा रेल के माध्यम से करवाने की भी कार्यवाही की जाए।

महोदय, धान की खरीदारी में एफसीआई अधिकारियों के उदासीन रवैये के चलते धान की खरीद बिहार में नहीं हो सकी है। खाली जूट का बोरा नहीं होने के कारण उन्होंने किसान के धान की खरीद नहीं की, बल्कि बिचौलियों के माध्यम से अच्छी कमाई की। अतः मैं मांग करता हूं कि इसमें संलिप्त पदाधिकारियों पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए।

*t33

Title: Need to expedite the work on NHDP-3 in Bihar.

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण): महोदय, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में जो कमजोरी हो रही है, उसकी ओर मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

महोदय, एनएचडीपी फेज-1 स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को वर्ष 2007 में पूरा करना था, लेकिन सासाराम, बिहार की सोन नदी पर पुल अभी भी अधूरा है। एनएचडीपी फेज-2 पूर्वी-पश्चिमी कोरीडोर बिहार में 513 किलोमीटर है। 15 पैकेजों में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। पहला पैकेज वर्ष 2002 में पूरा करना था, अभी तक मात्र एक पैकेज यातायात के लिए खोला गया है। शेष पैकेजों में 25 प्रतिशत भी काम पूरा नहीं हुआ है। उसमें काम करने वाली एजेंसियों में से चार के बारे में बिहार सरकार ने लिखकर भी भेजा है, उन एजेंसियों से समाप्त करके उनसे काम लिया जाए, क्योंकि उनका काम बिलकुल नगण्य है।

महोदय, 26 जून 2004 को भारत सरकार के सम्माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री पटना गए थे, उन्होंन 890 किलोमीटर एनएच को एनएचडीपी के फेज-3 में चार लेन में चौड़ीकरण की घोषणा पटना में की थी और इसे लिया भी गया।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Thank you. Please take your seat.

...(*Interruptions*)

श्री राधा मोहन सिंह : महोदय, यही तो मेरा विषय है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You cannot make a long speech like this. You have raised the issue.

...(*Interruptions*)

श्री राधा मोहन सिंह : इन्होंने जो घोषणा की थी...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You are reading a statement. You can place it on the Table of the House, and that will form part of the record. Otherwise, you can speak in one sentence.

...(*Interruptions*)

श्री राधा मोहन सिंह : महोदय, उसकी घोषणा किए हुए साढ़े चार वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन उसे अभी तक शुरू नहीं किया गया है। पटना - बख्तियारपुर, मोतीहारी-रक्सौल एवं पटना-गया डोभी के लिए अभी तक डीपीआर भी फाइनल नहीं हुआ है । एनएच की 1935 किलोमीटर सड़क के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। बिहार की सरकार चार सौ करोड़ रूपये अपने खजाने से निकालकर खर्च कर रही है। मैं आपके माध्यम से इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

*t34

Title: Impact of weak monsoon on the Kharif output in the country particularly in Andhra Pradesh.

MR. CHAIRMAN: Dr. K.S. Rao, your matter has already been raised today while having the discussion under Rule 193.

DR. K.S. RAO (ELURU): Yes, Sir, I know. I would not take much time. I would come to the main points only.

Andhra Pradesh is one of the States, which has been affected by weak monsoon. The main reason is that the sowing season in Andhra Pradesh is from June to August and the coastal districts of Andhra Pradesh would get cyclones in November. Andhra Pradesh being the rice bowl of the country, it would be badly affected because of the weak monsoon.

Keeping all these things in view, I would request the Government to provide more funds for Andhra Pradesh through AIBP, about which the hon. Minister has already mentioned in his speech that he has provided Rs. 9,700 crore in the whole country.

Sir, similarly, the price of palmolein has come down from Rs. 6,300 to Rs. 3,800, and all the farming community ran after it and cut down their mango gardens, and are now repenting for going in for palmolein. Therefore, I would request the hon. Agriculture Minister to immediately intervene in the market and take steps to increase the price of palmolein to at least, Rs. 4,800.

My last point is that the Government of Andhra Pradesh has undertaken Jalayagnam activity in a big way, and there are projects, which can be completed immediately. The Pollawaram project is one project, which is linking Godavari and Krishna rivers.

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister has already replied while speaking on the discussion under Rule 193.

DR. K.S. RAO : So, my request is that the Pollawaram project must be treated as a national project.

*t35

Title: Need to enhance crop assistance under CRF norms to address the problems being faced by farmers in the country.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK) : Sir, I have already raised the matter relating to the CRF.

MR. CHAIRMAN: This has also been covered in the reply of the hon. Minister. So, please be very brief.

SHRI B. MAHTAB : Yes, Sir. The hon. Minister was kind enough to say that after the Session, the Government is going to consider it. My demand is that the CRF relief amounts that are being provided as assistance at the rate of Rs. 4,000 per hectare for irrigated area and Rs. 2,000 per hectare for non-irrigated land, should be raised as Rs. 10,000 per hectare for irrigated area and Rs. 5,000 per hectare for non-irrigated areas. This is my demand. I think, the Minister present here can communicate this demand to the concerned Minister when it is taken up by the Government.

*t36

Title: Regarding Prof. Sabbarwal murder case of Ujjain, Madhya Pradesh.

श्री सज्जन वर्मा (देवास): सभापति महोदय, आज से ठीक तीन साल पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN :Just raise the issue. No allegations can be levelled. Only mention the matter and sit down.

श्री सज्जन वर्मा : सभापति महोदय, यह बड़ा इम्पोरटेंट प्रश्न है, गुरु और शिष्य के संबंध के बारे में है। एक प्रोफेसर की हत्या तीन साल पहले विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए लोगों के द्वारा कर दी जाती है।..(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि नागपुर न्यायालय में जो निर्णय हुआ, न्यायाधीश ने निर्णय देते वक्त यह कहा कि मैं आरोपियों को बरी तो कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन दुखी है। इसलिए दुखी है...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: What is it that you want to raise? You make your point.

...(*Interruptions*)

श्री सज्जन वर्मा : सभापति महोदय, यह बहुत इम्पोरटेंट प्रश्न है। न्यायाधीश ने कहा कि इस निर्णय को देते हुए मेरा मन दुख रहा है। अभियोजन पक्ष और पुलिस ने ठीक ढंग से सबूत पेश नहीं किए, यह इसलिए हुआ कि...

*(Interruptions) â€¦**

MR. CHAIRMAN :This will not go on record. Mr. Verma, please take your seats.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : No. This cannot be raised in the House. Please understand that such things cannot be raised in the House. Take your seat, please.

(Interruptions) â€¦ *

MR. CHAIRMAN: This is not allowed. This will not go on record.

(Interruptions) â€¦ *

MR. CHAIRMAN: Mr. Verma, please take your seat.

Now, Mr. Ganesh Singhji.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Mr. Verma, what you are saying is not allowed. This will not go on record. You can take your seat.

(Interruptions) â€¦ *

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except what Mr. Ganesh Singh speaks.

*(Interruptions) â€¦**

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please take your seat. I have not allowed you. I have only allowed, Mr. Ganesh Singh.

...(*Interruptions*)

---

* Not recoreded.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): He is demanding CBI inquiry into the matter. You may consider it...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Ganesh Singh, please start speaking. Otherwise, you would lose your chance.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Mr. Verma, please take your seat. It is not going on record.

*(Interruptions) â€¦ *

20.00 hrs.

MR. CHAIRMAN : No, please take your seat. I am repeatedly telling you to take your seat. Please take your seat. This is not going on record.

*(Interruptions) â€¦ *

*t37

Title: Need to provide air connectivity linking Satna with Delhi, Bhopal and Mumbai.

श्री गणेश सिंह : सभापति महोदय, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र सतना की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरा लोक सभा क्षेत्र सतना सीमेंट उद्योग, पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। देश में जितना सीमेंट उत्पादित होता है उसका एक-तिहाई सीमेंट मेरे लोक सभा क्षेत्र में उत्पादित होता है। बड़े-बड़े उद्योग वहां लगे हैं और अभी भी अनेक उद्योग लगने जा रहे हैं। इसी तरह चित्रकूट एवं मैहर में हर वर्ष लाखों यात्री एवं देशी-विदेशी पर्यटक आते-जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जो हवाई अड्डा बना था, वह प्रदेश सरकार के अधीन मौजूद है। मैंने लगातार मांग की है कि सतना को दिल्ली, भोपाल एवं मुम्बई की हवाई सेवाओं से जोड़ा जाए। आज मैं पुनः यह मांग कर रहा हूं। उस क्षेत्र में हवाई यात्रा करने वालों की कतई कमी नहीं है। अभी लोग खजुराहो, जबलपुर एवं भोपाल से हवाई यात्राएं कर रहे हैं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

*t38

Title: Regarding Ravghat project of Bhilai Steel Plant.

कुमारी सरोज पांडेय (दुर्ग) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सदन का ध्यान आपके माध्यम से भिलाई इस्पात संयंत्र, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है और जहां पर 40 हजार कर्मचारी काम करते हैं और आसपास की करीब 5 लाख आबादी इस पर निर्भर है, उसकी ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहती हूं कि राव घाट परियोजना, जो एन.डी.ए. की सरकार में बड़ी तेजी के साथ चल रही थी, लेकिन अब यू.पी.ए. सरकार के समय में यह योजना केवल भौतिक स्तर पर, कागजों में सिमट गई है। आज इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, उसके लौह अयस्क की जो खदानें हैं, वे समाप्ति की ओर हैं। अगर भविष्य में यह योजना पूरी नहीं हो पाई, तो उस क्षेत्र का विकास रुक जाएगा। चूंकि 12 वर्षों से यह योजना कागजों पर है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

*t39

Title: Need to declare Teli, Gop and MairaCastes of Jharkhand as extremely backward castes.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : सभापति महोदय, देश में, खासकर के झारखंड में कई ऐसी जातियां हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी रोजी-रोटी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों को ऐसी जातियों के सामाजिक स्तर की नियमित समीक्षा करनी चाहिए और सरकार को इस पर चिन्तन करना चाहिए। महोदय, कुछ लोग तो सरकारी सहायता से ऊपर उठ जाते हैं, परन्तु अधिकांश जातियों को सरकारी रियायतों का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति की नियमित समीक्षा नहीं हो पाती है। आज झारखंड में तेली, गोप और मैरा जाति के जो लोग हैं, उनका पलायन हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इन जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की नियमित समीक्षा हो और झारखंड में तेली, गोप और मैरा जाति को अत्यन्त पिछड़ी जाति में शामिल करने की व्यवस्था की जाए।

*t40

Title: Need to re-establish the ancient Nalanda University in Bihar.

MR. CHAIRMAN: Mr. Kaushalendra Kumar, your name was called this morning. You were not present. Please make your point very quickly.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सम्पूर्ण विश्व के ज्ञान की अलख जगाने वाला नालन्दा विश्वविद्यालय महज एक विश्वविद्यालय नहीं, अपितु शैक्षणिक संस्कृति और वैचारिक साधना का एक अनुपम केन्द्र था। पांचवीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इस शिक्षा केन्द्र का सानी समकालीन विश्व में कोई दूसरा विश्वविद्यालय नहीं था।

महोदय, उस विश्वविद्यालय में 10 हजार छात्र अध्ययन करते थे और 1 हजार शिक्षक थे। आप अन्दाज लगाएं कि वह कितना विशाल एवं भव्य रहा होगा। वैसे विश्वविद्यालय का फिर से पुनर्स्थापित करने का फैसला बिहार के मुख्य मंत्री ने लिया है और इस दिशा में काम काफी आगे बढ़ चुका है। बिहार सरकार द्वारा इस विश्वविद्यालय के लिए जमीन की भी व्यवस्था कर ली गई है। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि फिर से नालन्दा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*t41

Title: Need to take action against the officials of Urban Co-operative Bank, Bikaner (Rajasthan) for committing irregularities.

MR. CHAIRMAN: Shri Arjun Ram Meghwal Ji, you are allowed to raise your point. You cannot raise any allegation. You just make the point and sit down. आपने जो नोटिस दिया है, उसमें एलीगेशन्स हैं। उन्हें आप नहीं बोलें। You just raise the issue and then finish.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): Sir, thank you for allowing me to make my submission in 'Zero Hour'.

सभापति महोदय, मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। वहां लगभग 30 वर्ष पहले एक अरबन को-आपरेटिव बैंक स्थापित हुआ और हजारों

लोगों ने यह मानकर कि वह आर.बी.आई. के लाइसेंस के अन्तर्गत स्थापित हुआ बैंक है और नाबार्ड उसे फायनेंस करता है, अपना पैसा जमा कराया। मैं कहना चाहता हूं कि उनका पैसा उसमें जमा है, जिसकी रसीदें उनके पास हैं, लेकिन अरबन को-आपरेटिव बैंक के लोग यह कहते हैं कि Bank is under liquidation. उन्हें उनका पैसा वापस नहीं दे रहा हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उस अरबन को-आपरेटिव बैंक को उनके भरोसे मत छोड़ो। जिन नागरिकों ने उसमें बचत बैंक के माध्यम से अथवा एफ.डी.आर. के माध्यम से पैसे जमा कराए हैं, उनके पैसे वापस दिलाए जाएं। यह डयूटी तो सरकार निभा ही सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसा अन्याय नहीं हो और माननीय वित्त मंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि लोगों के साथ ऐसा अन्याय नहीं हो और आप इसमें हस्तक्षेप करें। लोगों का पैसा जमा है, उनके पास रसीदें हैं। वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं मिल रही है।

MR. CHAIRMAN : Thank you Meghwalji.

I thank all the hon. Members for raising these matters of urgent public importance.

The House stands adjourned to meet again at 11 a.m. on Wednesday, 29th July, 2009.

20.05 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Wednesday, July 29, 2009/Sravana 7, 1931 (Saka).

---

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

* Not recorded.

* Not recorded.